पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्थ सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि — 16 अग्रहायण, 1933 (श०)
07 दिसम्बर, 2011 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—08

(1) ग्रामीण कार्य विभाग	..	..	..	03
(2) पथ निर्माण विभाग	..	..	..	03
(3) जल संसाधन विभाग	..	..	..	02
			कुल योग ..	08

कार्रवाई नहीं करने का औचित्य

07. डॉ० इजहार अहमद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 जुलाई, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "780 करोड़ रुपये की सड़कें आई जांच के घेरे में" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पांच वर्ष में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 780 करोड़ रुपये से बनी 1596 कि०मी० लम्बी सड़कें बनने के साथ गुणवत्ता के अभाव में टूट रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण कार्य विभाग से बनी 300 करोड़ रुपये की 256 सड़कें 1725 कि०मी० और एन० सी० सी० से 480 करोड़ रुपये की 871 कि० मी० की लम्बी सड़कों की जांच का आदेश जिलाधिकारी, दरभंगा ने उक्त अवधि में दी है जिस पर आजतक कार्रवाई नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा उक्त अनियमित कार्यों के विरुद्ध दिए गए जांच के आदेश पर आजतक कार्रवाई नहीं किये जाने का क्या औचित्य है तथा सरकार इस पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पथों की लम्बाई

08. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अवस्थित कुल सड़क की लम्बाई 94009.42 कि०मी० है;

(2) क्या यह बात सही है कि कुल सड़क की लम्बाई में राज्य उच्च पथ श्रेणी का सड़क मात्र 3989 कि०मी० है जो कुल सड़क का मात्र 4.24 प्रतिशत है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य उच्च पथ श्रेणी के सड़कों की संख्या और लम्बाई में वृद्धि नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कार्य पूरा कराना

09. श्री सुमित कुमार सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सोनो प्रखण्ड के बटिया में बरनार जलाशय योजना की स्वीकृति 1976 में सरकार द्वारा दी गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1988 में ग्लोबल टेंडर को उक्त योजना के निर्माण हेतु कार्य आवंटित किया गया जिसपर आजतक दो अरब खर्च भी हो चुके हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त जलाशय से 80 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होनी है तथा 8 मेगावाट पन बिजली के उत्पादन का लक्ष्य है;

(4) क्या यह बात सही है कि आजतक उक्त निर्माण कार्य नहीं होने से प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र में उक्त निर्माण कार्य को पूरा कराने हेतु अपने पत्रांक 29 (आ०), दिनांक 7 मार्च, 2011 द्वारा पत्र लिखा है जिसपर आजतक कार्रवाई नहीं की गयी है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कार्य में विलम्ब करने वाले पर कार्रवाई करते हुए उक्त कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है ?

दोषी पर कार्रवाई

10. डॉ० अच्युतानन्द--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 अप्रील, 2011 के अंक में छपी खबर " धन की धुन पर नाचे नियम भूल" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में पथ संरक्षण और मरम्मत मद में 350 करोड़ की राशि आवंटित की गयी थी जिसमें से 120 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान सिर्फ ग्रामीण पथों की मरम्मती के लिए किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि 120 करोड़ की राशि पटना नगर निगम एवं अन्य निकाय क्षेत्रों में कर दी गयी और कई जगहों पर केवल रशीद लगाकर करोड़ों रुपये की निकासी कर ली गयी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त राशि की गलत ढंग से निकासी की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परियोजनाओं का निर्माण

11. श्री अखनीश कुमार सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधना विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नेपाल से निकलनेवाली नदियों की बाढ़ से उत्तर बिहार को स्थाई निजात दिलाने के लिए 1991 में विशेष दल का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था, जिसकी अनुशंसा के आधार पर महत्वाकांक्षी हाई डैम योजना सप्तककोसी-सनकोसी के निर्माण का 1994 में ही निर्णय लिया गया था परन्तु अभीतक स्थल का चयन नहीं हो पाया जिसके कारण डी०पी०आर० भी नहीं बन पाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सप्तकोसी-सनकोसी हाई डैम का निर्माण नहीं होने के कारण उत्तर बिहार हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलने के लिए अभिशप्त है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से पहल करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

12. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अक्टूबर, 2010 तक सम्पर्क पथ की कुल लम्बाई 69,376 किलो मीटर है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सम्पर्क पथ में मात्र 9917 कि०मी० सड़क पक्की है एवं 59459 कि०मी० सड़क कच्ची है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 59459 कि०मी० कच्ची सड़क को कबतक पक्कीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ का चौड़ीकरण

13. श्री दाउद अली--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के सोनपुर पशु मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, जिसकी महत्ता आज भी बनी हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि आजादी के वर्षों बाद भी मेला परिसर का पथ मात्र 10 फीट की है, जिससे व्यापारियों, वाहनों एवं आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोनपुर पशु मेला परिसर पथों को डबल लेन में परिवर्तित करना चाहती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

14. श्री आनन्दी प्रसाद यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 और 2011 में अररिया जिला के अररिया, सिकटी, पलासी, कुर्साकांटा, फारबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज, भरगामा प्रखण्ड के 218 पंचायतों में मनरेगा के तहत 60 करोड़ की राशि वृक्षारोपण करने में खर्च की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि वृक्षारोपण का कार्य ससमय एवं मानक के अनुसार स्तरीय पौध निविदा के माध्यम से क्रय नहीं करने तथा सुरक्षा की अनदेखी करने के कारण 99 प्रतिशत वृक्ष सुख गये हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि मानव दिवस सृजन में कागजी मास्टर रोल का संधारण कर 59 करोड़ राशि पदाधिकारियों एवं बिचौलियों के बीच बंदरबांट कर दिया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मनरेगा के माध्यम से सरकारी राशि की क्षति की जांच कराते हुए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 7 दिसम्बर, 2011 (ई०)।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

वि०स०मु० (एल०ए०), 60-डी०टी०पी०--450